

इंदौर, शुक्रवार 03 अप्रैल 2026

वर्ष : 5 अंक : 134

पृष्ठ : 6 मूल्य : 2

dainikindoresanket.com

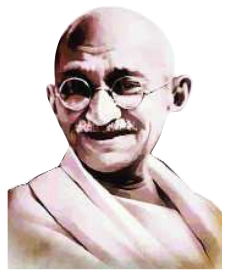
dainikindoresanket

dainikindoresanket

dainikindoresanket24@gmail.com

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत



राष्ट्रपिताको नमन...

good friday



बलिदान, क्षमा और मानवता का संदेश : गुड फ्राइडे आज

अक्षय की बात
अपनी के साथ

आज दुनियाभर में ईसाई समुदाय द्वारा गुड फ्राइडे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन ईसा मसीह के बलिदान और मानवता के लिए दिए गए उनके सर्वोच्च त्याग की याद दिलाता है।

माना जाता है कि इसी दिन उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे को 'अच्छा' इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईसा मसीह ने अपने कष्ट और मृत्यु के माध्यम से मानव जाति के पापों का प्रायश्चित्त किया और प्रेम, क्षमा व करुणा का संदेश दिया। यह दिन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ईमान को धैर्य, सहनशीलता और परोपकार का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। देश-विदेश के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। श्रद्धालु उपवास रखते हुए प्रभु की आराधना करते हैं और उनके बलाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। कई स्थानों पर जुलूस और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से ईसा मसीह के जीवन और उनके अंतिम क्षणों को जीवंत किया जाता है। गुड फ्राइडे केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणा है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में कितनी सहनशीलता, प्रेम और क्षमा को अपनाते हैं।

दिल्ली की 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की राजज एलेन्यू कोर्ट ने गुरुवार सुबह 11 बजे भारतीय को सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू की और दोपहर 12:41 बजे 3 साल की सजा का फैसला सार्वजनिक हुआ। हालांकि, कोर्ट ने अपील के लिए 60 दिन की मोहलत देते हुए सजा निलंबित रखी है। सहआरोपी बैंक क्लर्क रघुवीर प्रजापति को भी दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने भारतीय को आपराधिक साजिश (धारा 120B) और धोखाधड़ी व जालसाजी (धारा 420, 467, 468, 471) में दोषी माना। उन्हें दो धाराओं में 3-3 साल और एक धारा में 2 साल की सजा सुनाई है। इससे उनकी विधायकी पर खतरा बना हुआ है।

वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, अपील के लिए उन्हें 60 दिन मिलेंगे। अगर हाईकोर्ट से सजा पर स्थगन (स्टे) मिल जाता है, तो उनकी विधायकी बरकरार रह सकती है।

अंदर के पन्नों पर...

रणजीत हनुमान के दरबार में महाभोज



पेज-2

शिवाजी मार्केट की 16 दुकानें टूटेंगी



पेज-6

न्यूज ब्रीफ

- मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, बागडोगरा एयरपोर्ट से पुलिस ने दबोचा

- परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी INS अरिंदमन आज भारतीय नौसेना में होगी शामिल

- मिडिल ईस्ट : ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमले में 8 नागरिकों की मौत, 95 घायल

- सिविलियन साइट पर हमले करके अमेरिका जंग में अपनी हार का दे रहा संदेश : ईरान

- रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने पीएम मोदी से की मुलाकात, रणनीतिक संबंधों पर हुई चर्चा

- अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को पछेड़ने को कहा

टेलर की कटिंग



सत्ता पर संगठन हावी से इंदौर के नेताओं के पर कटे

'गौरव' का गौरव घटा, सुमित के हाथ कुछ नहीं लगा

आशीष गुप्ता : 9425064357

इंदौर/भोपाल • दैनिक इंदौर संकेत भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी में इंदौर के 8 युवा चेहरों को जगह मिली है। सूची में शामिल इन नामों के बाद टेलर की कटिंग से इंदौर के कई नेताओं के पर काट दिए गए हैं। इंदौर में जो भी नियुक्तियां हुई हैं, उसमें संघ एवं संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखा जाए प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे केवल एकमात्र नाम नयन दुबे को महामंत्री बनाने के लिए अड़े थे और उनके गौरव को घटाते हुए उनके कट्टर समर्थक को सोशल मीडिया पर फेंक दिया। शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा बड़ी-बड़ी बातों के लिए माने जाते हैं। उनके कट्टर समर्थक मयूरेश पिंगले, अक्षय चौधरी, रोहित चौधरी के लिए लाख कोशिश करने के बाद भी कार्यकारिणी में जगह नहीं दिला पाए। लगता है अब उनका दंभ टूट गया होगा। रमेश मेंदोला एवं मालिनी गौड़, महेन्द्र हाईडिया भी अपने किसी समर्थकों को एंटी नहीं दिला सके।

विवेक शर्मा जिन्होंने उपाध्यक्ष पद पाया है, उनके लिए मध्य प्रांत के एक प्रचारक ने वोटो कर रखा था। उन्होंने अपने कट्टर समर्थक डॉ. निशांत खरे को इसकी जिम्मेदारी दे रखी थी। जहां तक घनश्याम सिंह को मंत्री पद मिला है, उसके पीछे भी अखिल विद्यार्थी परिषद् संगठन के क्षेत्रीय

प्रचारक की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है, जबकि घनश्याम सिंह को इंदौर के किसी भी नेता ने अपनी तरफ से नाम नहीं दिया था।

इंदौर से शामिल नाम और उनके सियासी संकेत

विवेक शर्मा : संगठन में सक्रिय रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी मौजूदगी कुछ खास राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ी है। उनकी नियुक्ति के अंदर डॉ. निशांत खरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही और मध्य प्रांत के एक प्रचारक का विशेष योगदान रहा।

अंकित रावल : यह भी टीनू जैन की सिफारिश के दम पर बने हैं। टीनू जैन ने इनके लिए वीडो शर्मा से सिफारिश करवाई थी।

नयन दुबे : युवा मोर्चा के कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय चेहरा। प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे की सिफारिश के बावजूद इन्हें मात्र सोशल मीडिया का प्रभारी बनाकर गौरव के पर काट दिए गए हैं। ऐसा लगता है हितानंद शर्मा के जाने के बाद गौरव का गौरव कम हो गया है।

घनश्याम सिंह : इनका नाम सामने आते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हुई। माना जा रहा है कि अखिल भारतीय

विद्यार्थी परिषद् के क्षेत्रीय प्रचारक की सिफारिश के कारण इन्हें पद की प्राप्ति हुई है। यह भी संगठन की नियुक्ति ही मानी जा रही है।

अमन यादव : सामाजिक और जातीय समीकरण के लिहाज से अहम चेहरा। इनकी नियुक्ति को ओबीसी समीकरण साधने की रणनीति से जोड़ा जा रहा है। यह आकाश विजयवर्गीय के समर्थक हैं।

भावेश दवे : संगठन और वैचारिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। यह महापौर पुष्पमित्र भार्गव के खास समर्थक माने जाते हैं। महापौर के हाथ एकमात्र पद की प्राप्ति हुई है।

स्निग्धा मोर्य : महिला प्रतिनिधित्व और युवा नेतृत्व के संतुलन में इनका चयन अहम माना जा रहा है। इनके पीछे महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति दिखती है।

आशीष हाईडिया : स्थानीय राजनीति में तेजी से उभरता नाम। सूत्रों के अनुसार इनकी पकड़ प्रभावशाली राजनीतिक समूहों के साथ जबरन मानी जाती है।

इस पूरी सूची को देखें तो साफ नजर आता है कि सत्ता पर संगठन काफी हावी रहा। इन नियुक्तियों में मध्य प्रांत के प्रांत प्रचारक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के क्षेत्रीय प्रचारक महत्वपूर्ण पद ले जाने में सफल रहे। स्थानीय नेताओं को केवल झुनझुना हाथ में आया है।

जीतू पटवारी देर रात पहुंचे विधानसभा सचिवालय राजेन्द्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म



इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल • विधानसभा सचिवालय ने दतिया विधायक राजेन्द्र भारती की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। कल देर रात रात करीब साढ़े दस बजे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंचे। इसके बाद सचिवालय खोलकर भारती की सीट रिक्त घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई।

इधर, घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व विधायक पीसी शर्मा भी रात में ही विधानसभा पहुंच गए। दोनों नेता सीधे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के चैंबर में पहुंचे और पूछा कि इतनी रात में विधानसभा क्यों खोली गई? शर्मा के बिना जवाब दिए वहां से निकलने के बाद पटवारी ने आरोप लगाया कि भारती की सदस्यता खत्म करने के लिए यह कदम भाजपा के

फर्जी दस्तावेजों से FD का ब्याज निकाला

घटनाक्रम की शुरुआत 1998

में तब हुई, जब श्याम सुंदर संस्थान को अध्यक्ष और राजेन्द्र भारती की मां सावित्री श्याम ने दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी की थी। साल 1998 से 2001 के बीच राजेन्द्र भारती उसी बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे। वे श्याम सुंदर संस्थान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य भी थे। भारती ने क्लर्क रघुवीर प्रजापति के साथ मिलकर बैंक के रिकॉर्ड में हेरफेर की और एफडी की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी। इसके बाद सालाना 13.5% की दर से ब्याज के 1,35,000 रुपए साल 1999 से 2011 के बीच निकाले गए।

बीजेपी नेता ने किया मामले को उजागर

3 मार्च 2011 को बैंक अध्यक्ष बने भाजपा नेता पुष्प पुजारी मामले को सामने लाए। सहकारिता विभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक अभय खरे ने जांच की, जिसमें एफडी पर ऑडिट आपत्ति दर्ज हुई। 2012 में भारती ने बैंक से एफडी की राशि मांगी, लेकिन ऑडिट आपत्ति के चलते भुगतान से इनकार किया गया। भुगतान न मिलने पर भारती उपभोक्ता फोरम पहुंचे, जहां से राहत नहीं मिली।

राज्य उपभोक्ता फोरम से राहत

मिलने के बाद मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद 2015 में तत्कालीन कलेक्टर प्रकाशचंद्र जांगड़े ने आपराधिक मामला दर्ज कराने की पहल की। कोर्ट के आदेश पर आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ।

2 साल या ज्यादा सजा पर विधायकी जाने का प्रावधान

कानूनी प्रावधानों के अनुसार 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायकी स्वतः जा सकती है। दतिया विधायक राजेन्द्र भारती को 3 साल की सजा हुई है। सीट खाली होने पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि, हाईकोर्ट से सजा पर स्टे मिलने पर राहत संभव है। विधायक के बेटे अनुज भारती ने बताया कि उनके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे और जमानत के लिए आवेदन देंगे। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को दिल्ली MP-MLA कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े मामले में बुधवार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने राजेन्द्र भारती को तिहाड़ जेल भेज दिया है।

कमलनाथ का फिर जागा 'भाजपा' प्रेम

इंदौर संकेत प्रतिनिधि



भोपाल • मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है। छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ से जब मीडिया ने एलपीजी की किल्लत को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की कमी नहीं है। कमलनाथ ने कहा, 'यह अव्यवस्था है। ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन माहौल बना दिया गया है कि कमी है।' उनका यह

डोलाछाप डॉक्टर का विलनिक सील

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • पाटनीपुरा मेन रोड स्थित एक कथित क्लिनिक पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। यहां बिना मेडिकल डिग्री के मरीजों का इलाज करने और खासतौर पर बवासीर के मरीजों से पैसे वसूलने का आरोप था। पाटनीपुरा स्थित 'राव दवाखाना' के खिलाफ पहली शिकायत 2023 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को की गई थी। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में भी मामला उठाया गया, लेकिन करीब तीन साल तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। करणी सेना के संगठन मंत्री मानसिंह राजावत ने बताया कि हमारे कार्यालय पर शिकायतकर्ताओं ने आकर पूरी जानकारी दी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह दीक्षित, प्रदेश महासचिव मनीष सिंह सिसौदिया सहित अन्य कार्यकर्ता यहां पहुंचे। कलेक्टर शिवम वर्मा को मौके से कॉल लगाया इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दवाखाने को सील कर दिया।

सत्तन गुरु की बेटी कनुप्रिया का पीएम को खुला पत्र

घटना को 'सोची-समझी साजिश' बताया; निष्पक्ष जांच की मांग

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • 29 मार्च को दशहरा मैदान पर आयोजित नगर तिनाम के भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन के साथ हुई कथित अपमानजनक घटना अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। सत्तन गुरु की बेटी कनुप्रिया सत्तन, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई हैं, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश करार दिया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

कनुप्रिया सत्तन ने अपने पत्र में लिखा है कि यह घटना न केवल उनके पिता के साथ अपमानजनक है, बल्कि लोकतांत्रिक



मूल्यों के विरुद्ध भी है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम में अनावश्यक विवाद पैदा करने की सोची-समझी चाल बताया है। कनुप्रिया ने पत्र में उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए तैयार की गई मंच अतिथि सूची

माजपा का डैमेज कंट्रोल, कांग्रेस का हमला

घटना के अगले दिन भाजपा इंदौर शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सत्तन गुरु के घर पहुंचे। उन्होंने बंद कमरे में लंबी बातचीत की और कहा, 'सत्तन गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम 25 बार माफी मांग लेंगे।' महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी व्यक्तिगत रूप से फोन कर खेद जताया और गलती से पर्वी न लग पाने की बात कही। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस मौके को भुनाया। कांग्रेस के जिला सेवादा कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश जोशी और अन्य नेताओं ने सत्तन गुरु के घर पहुंचकर उन्हें तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया और भाजपा पर तीखा हमला बोला।

में सत्यनारायण सत्तन का नाम पूर्व निर्धारित रूप से शामिल था। कार्यक्रम स्थल पर उनकी नामांकित सीट से नाम की स्लिप हटाए जाने की घटना जानबूझकर की गई कार्रवाई प्रतीत होती है। उनका कहना है कि यह एक

सुनियोजित प्रयास लगता है, जिसका उद्देश्य मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अनावश्यक विवाद और व्यवधान उत्पन्न करना था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम एक मुख्यमंत्री-विरोधी मंत्री के इशारे पर किया गया

बताया जा रहा है, जिससे राजनीतिक असहजता पैदा हो सके। उन्होंने यह भी लिखा कि सत्तन गुरु ने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहकर संगठन, विचारधारा और राष्ट्रहित के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पत्र में कनुप्रिया ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। 29 मार्च को नर्मदा चौथे चरण से जुड़े बड़े सरकारी कार्यक्रम में मंच पर 69 अतिथियों की सूची तैयार की गई थी। सूची में सत्तन जी का नाम 26वें नंबर पर था और उनकी कुर्सी भी लगाई गई थी। लेकिन मंच पर पहुंचते ही एक कार्यकर्ता ने उन्हें रोक लिया और कहा कि सूची में नाम नहीं है। नाम की स्लिप गायब थी।

न्यूज ब्रीफ

श्रीमद्भागवत कथा 7 से

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • वृंदावन निवासी प्रकांड विद्वान श्री श्री 108 श्री डॉ मनोज मोहन शास्त्री के मुखार बिंद से 7 से 14 अप्रैल तक आयोजित हो रही हैं। श्रीमद्भागवत प्रसंग-दि. 7 अप्रैल- श्रीमद्भागवत माहात्म्य शुभारम्भ, 8 अप्रैल- श्रीध्रुव चरित्र 9 अप्रैल- प्रह्लाद चरित्र नृसिंहावतार, 10 अप्रैल- श्रीकृष्ण जन्मोत्सव 11 अप्रैल- श्रीकृष्ण बाललीलाएँ एवं गिरिराज पूजन 12 अप्रैल- महारास एवं रुक्मिणी विवाह 13 अप्रैल- श्रीशुकदेव विदाई एवं व्यास पूजन होगा। श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन विश्व प्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर इंदौर में हो रही हैं। वृंदावन निवासी प्रकांड विद्वान भगवताचार्य श्री श्री 108 श्री आचार्य डॉ मनोज मोहन शास्त्री प्रतिदिन दोपहर से शाम 6:00 बजे तक मन्दिर परिसर के दौलत राम छबछरिया प्रवचन हाल में श्रवण करावेंगे।

स्कार यात्रा का नेतृत्व गौ माता द्वारा किया जाएगा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • परशुराम जयंती के अवसर पर सात दिवसीय प्रभात फेरी के साथ भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। श्री परशुराम सेना इंदौर प्रकाश शर्मा (पम्पी), दीपक शर्मा, अनिल तिवारी ने बताया कि परशुराम जयंती धूमधाम से बनाई जाएगी। 18 अप्रैल को संस्कार यात्रा बड़े गणपति से राजवाड़ा निकलेगी जिसका नेतृत्व गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज अपनी यात्रा निकलेगा। गौतम तिवारी, पंकजराज तिवारी, रिदेश शर्मा ने बताया कि परशुराम जयंती के अवसर पर सात दिनों से प्रभात फेरी इंदौर शहर के विभिन्न ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में जाएगी साथ ही भगवान परशुराम जी सभी की आराध्य हैं और भगवान विष्णु के 24 अवतार में से एक अवतार है। इसलिए सभी के आराध्य हैं। उपरोक्त प्रभात फेरी 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जाएगी।

शास. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में सहायक प्राध्यापक पदों के लिए प्रशिक्षण सम्पन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में सहायक प्राध्यापकों और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विषयों के इंटरव्यू हेतु प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिदिन 100 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुये एवं योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त किया गया। उक्त कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान का प्रशिक्षण एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा संबंधित सभी विषयों के साक्षात्कार से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

गर्मी के मौसम में पशुओं से कार्य लेने पर प्रतिबंध, आदेश जारी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • गर्मी के मौसम को देखते हुए पशुपालन एवं डेयरी विभाग इंदौर द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गर्मी के दौरान पशुओं के उपयोग पर दोपहर के समय प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश के अनुसार एक अप्रैल से 10 जुलाई तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच, जब तापमान अधिक रहता है, उस अवधि में भार वाहक पशुओं से किसी भी प्रकार का कार्य लेना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान बैलगाड़ी, तांगा, ऊंटगाड़ी, भैंसगाड़ी, खच्चर, टट्टू एवं गर्धों पर वजन डोने या सवारी कराने से पशुओं के बीमार होने या मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पशु मालिकों से अपील की गई है कि वे इस अवधि में पशुओं को कार्य में न लगाएँ। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित पशु मालिकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।

रणजीत हनुमान के दरबार में महाभोज : 80 हजार भक्तों के लिए तैयार होगी प्रसादी, व्यवस्था ऐसी की घर पर ले जा सकेंगे प्रसाद

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • इंदौर के प्राचिन रणजीत हनुमान मंदिर में 7 अप्रैल को भंडारा होगा। भंडारे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 80 हजार भक्तों के लिए प्रसादी तैयार की जाएगी। खासबात यह रहेगी कि ये चलित भंडारा होगा, यानी भक्त आकर पैकेट में प्रसादी लेकर अपने घर जा भी सकते या बाहर खड़े होकर खा भी सकते हैं। 6 अप्रैल को सुबह भट्टी पूजन के बाद प्रसादी बनने का काम मंदिर परिसर में ही शुरू हो जाएगा।



हनुमान जन्मोत्सव के बाद पहले मंगलवार को ये भंडारा किया जाता है। सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस बार 80 हजार भक्तों के लिए प्रसादी तैयार की जाएगी। पहले भंडारे का स्वरूप अलग हुआ करता था, मगर व्यवस्थाओं को देखते हुए इसके

स्वरूप में बदलाव कर दिया गया है और इसे चलित कर दिया है। बता दें कि मंदिर में दो बार भंडारे का आयोजन किया जाता है। एक हनुमान जन्मोत्सव के बाद और दूसरा आंवला नवमी पर।

पहले बैठाकर भक्तों को दी जाती थी प्रसादी-कुछ साल पहले तक मंदिर परिसर के ग्राउंड में ही भक्तों को बैठाकर प्रसादी दी जाती थी। भक्तों के लिए बढ़िया बैठक

व्यवस्था की जाती थी, जहां पर महिला व पुरुष अलग-अलग बैठकर प्रसादी ग्रहण करते थे, जिसके कारण मंदिर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती थी। कई बार धक्का-मुक्की की नौबत आ जाती थी। भक्तों को प्रसादी लेने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था, जिसे देखते हुए इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया और चलित भंडारा शुरू हो गया।

पैकेट में लेकर जा सकते हैं प्रसादी-चलित भंडारे में भी महिला-पुरुषों की अलग-अलग लाइन लगती है। इसमें भक्त जैसे ही ग्राउंड परिसर में आते हैं उन्हें हाथ में थाली का पैकेट दे दिया जाता है, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें पुड़ी, सब्जी, भजिए, नुक्ति की प्रसादी थाली में दे दी जाती है, जिसके बाद वे पैकेट को बंद कर अपने साथ ले जा सकते हैं या

6 अप्रैल को भट्टी पूजन के साथ शुरू होगा प्रसाद बनना

पंडित दीपेश व्यास ने बताया कि 6 अप्रैल को सुबह भट्टी पूजन के साथ भंडारे की प्रसादी बनना शुरू हो जाएगी। अलग-अलग जगह से सब्जियां मंदिर परिसर में आएंगी। जिसके बाद महिला मंडल की सदस्यों द्वारा सब्जियों को सुधारा जाएगा। सब्जियों को कटिंग की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नुक्ति का प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा। रामभाजी बनाई जाएगी। ये काम लगातार जारी रहेगा और भंडारे की सभी चीजें बनाई जाएंगी। 7 अप्रैल को भगवान को भोग लगाने व आरती के बाद शाम 6.30 बजे से भंडारे की शुरुआत हो जाएगी।

परिसर के बाहर खड़े होकर खा भी सकते हैं। इस व्यवस्था से मंदिर के बाहर भीड़ नहीं लगती और प्रसादी लेने में भी भक्तों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है।

80 किंवदंतल आटे से बनेगी पुड़ी-मंदिर के पुजारी पं.व्यास ने बताया कि मंदिर की परंपराानुसार हनुमान जन्मोत्सव के बाद जो मंगलवार आता है इसी दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है।

लगभग 80 हजार भक्तों के लिए भोजन प्रसादी तैयार की जाएगी। चलित व्यवस्था रहेगी। महिला-पुरुषों की अलग-अलग लाइन रहेगी। प्रसादी में पुड़ी, रामभाजी, नुक्ति व भजिए का प्रसाद दिया जाएगा। इसे तैयार करने में 80 किंवदंतल आटा, 15 किंवदंतल बेसन, 90 डिब्बे शुद्ध घी और 200 डिब्बे मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर प्रसादी तैयार की जाएगी।

फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू

बिजासन टेकरी सहित तीन स्थानों पर भीषण आग, ताहनों को फूँका

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • शहर में देर रात तीन अलग-अलग स्थानों पर आगजनी की घटनाओं से हड़कंप मच गया। बिजासन टेकरी पर घास में भीषण आग लग गई, वहीं तेजाजी नगर में एक बाइक जलकर खाक हो गई। उधर बाणगंगा क्षेत्र में बदमाशों ने कार और दो बाइक में आग लगा दी। सभी घटनाओं में फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।



बुधवार रात करीब 10 बजे बिजासन टेकरी स्थित सेंट्रल स्कूल के पास मैदान में घास में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए पेड़-पौधों तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में लगभग 10 हजार लीटर पानी का उपयोग किया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। तेजाजी नगर में खड़ी बाइक रात करीब 1:30 बजे तेजाजी नगर क्षेत्र में जलकर खाक लिम्बोदी गेट के सामने खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी बाइक जलकर नष्ट हो गई। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई। हालांकि तब तक वाहन

पूरी तरह जल चुका था। इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को नहीं मिल सकी। बाणगंगा थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी किला मैदान इलाके में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी दो बाइक और एक कार में आग लगा दी। फरियादी रवींद्र पाल को शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार... बदमाशों ने बाइक से पेट्रोल निकालकर वाहनों में आग लगाई। घटना में भागवत राव और प्रेमसिंह की बाइक जलकर खाक हो गई, वहीं कार को भी नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी सुबह लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

निजी ट्यूबवेल और हाइड्रेट पर क्लोरिनेशन के लिए लोगों को करें प्रेरित आयुक्त की कार्रवाई, तीन इंजीनियरों को नोटिस, वेतन काटा, होगी जांच

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सीटी बस सभाकक्ष में जलप्रदाय, सीवेज, सीएम हेल्पलाइन, इंदौर 311 एप, स्वच्छ सर्वेक्षण और ग्रीष्मकालीन व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त ने साफ किया कि गर्मी के मौसम में नागरिकों को स्वच्छ और प्यास जल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने शासकीय ट्यूबवेल के साथ-साथ निजी ट्यूबवेल और हाइड्रेट पर भी क्लोरिनेशन का सुनिश्चित कराने के लिए नागरिकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। **टैंकरों पर जीपीएस सिस्टम लगाएँ**-क्लोरिनेशन संप्लानिंग में लापरवाही पाए जाने पर पीएचई विभाग के तीन सहायक यंत्री-राहुल रघुवंशी, दौलत सिंह गुड्डिया और शिव दत्त व्यास को शोकाज नोटिस



जारी करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने पानी की टंकी से लेकर अंतिम छोर तक क्लोरिनेशन का रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में रखने के निर्देश भी दिए। इसी प्रकार रेस्टोरेशन कार्य की खराब स्थिति पर सख्ती दिखाते हुए जून 12, वार्ड 59 में सीवेज कार्य के बाद संतोषजनक रेस्टोरेशन नहीं होने पर जलसुनवाई का तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। जल संकट से निपटने के लिए टैंकर व्यवस्था को भी सख्त बनाया गया। आयुक्त ने सभी टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाने और जीपीएस लोकेशन के आधार पर ही भुगतान करने के निर्देश दिए। **जनहित कार्य में लापरवाही**

बर्दाश्त नहीं होगी-जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने इसे लक्ष्य बनाकर पूरा करने और नागरिकों को रूप व रने वरत हावैरिस्टिंग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर रिचार्ज संचरणाएँ विकसित करने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही जलसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर वार्ड 9 उपयंत्री के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। आयुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी शिकायतों का समयसीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए।

हनीट्रैप का खुलासा, पूर्व सैन्य अधिकारी से दो लाख रु. की मांग

दो युवतियां और एक युवक गिरफ्तार

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • थाना बड़गोदा क्षेत्र के एक फार्म हाउस से हनीट्रैप का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें इंदौर की दो युवतियों और एक युवक ने मिलकर पूर्व सैन्य अधिकारी को षड्यंत्रपूर्वक फंसाकर उससे दो लाख रुपए की मांग की। बुधवार देर रात मामला बड़गोदा थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने सैन्य अधिकारी को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गुरुवार को तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी प्रकाश वास्करले के मुताबिक सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी, निवासी एमसीटी ब्वार्टर महू, जो वर्तमान एक सोची-समझी साजिश के तहत ब्लैकमेल रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया, जिसके जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया। इसके बाद सैन्य अधिकारी ने सीधे थाने पर सूचना दी। पिछले तीन-चार दिनों से

इंदौर निवासी एक युवती लगातार मोबाइल पर संपर्क कर रही थी और मिलने का दबाव बना रही थी। युवती ने अफसर को बातों में फंसा लिया, मिलने का स्थान कैलोड रोड स्थित रेम्बो रिसोर्ट में तय हो गया। गुरुवार शाम के लिए अधिकारी ने कमरा बुक कराया। फिर युवती और अधिकारी की मुलाकात महू के हरिफाटक पर हुई। यहाँ से दोनों रिसोर्ट साथ पहुंचे। रिसोर्ट में कुछ देर रुकने के दौरान महिला लगातार फोन और वॉट्सएप पर किसी से संपर्क में थी। इसके बाद जैसे ही वह अधिकारी के करीब आई, तभी अचानक बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो बाहर एक महिला और एक युवक खड़े थे, जिन्होंने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए सैन्य अधिकारी को पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी। उक्त लोगों ने अधिकारी से कहा कि यदि वह दो लाख रुपए नहीं देगा तो उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराएंगे।

वैज्ञानिक, खगोलविद और शोधार्थी करेंगे संवाद

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 3 अप्रैल को उज्जैन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'महाकाल: द मास्टर ऑफ टाइम' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का तारामंडल परिसर में शुभारंभ करेंगे। साथ ही उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। सम्मेलन 3 से 5 अप्रैल तक उज्जैन के समीप डोंगला डिजिटल प्लेनेटेरियम परिसर में आयोजित किया गया है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन और विचारक लेखक श्री सुरेश सोनी भी शामिल होंगे। बाबा महाकाल और सम्राट विक्रमादित्य की पावन नगरी उज्जैन प्राचीन काल से ही काल गणना और खगोल विज्ञान के अनुसंधान की वैश्विक धुरी रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक व शोधकर्ता यहां बौद्धिक समागम के लिये एकत्रित हो रहे हैं।

आलोक दुबे भाजपा के प्रदेश सहमीडिया प्रभारी नियुक्त

भाजपा नेताओं ने नियुक्ति पर दी बधाई

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन ने प्रदेश की मीडिया विंग की घोषणा की है। आलोक दुबे को प्रदेश मीडिया टीम में सह मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। आगामी वर्षों में होने वाले नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा की विचारधारा को समझने वाले मीडिया क्षेत्र के अनुभवी कार्यकर्ता आलोक दुबे को प्रदेश प्रवक्ता के स्थान पर भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी के रूप में मीडिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। पूर्व में 14 वर्षों तक इंदौर संभाग के संभागीय मीडिया प्रभारी के पद पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं। दुबे की नियुक्ति पर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावत, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, गोल्ड शुक्ला, मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, मधु वर्मा आदि ने बधाई दी है। भाजपा प्रदेश सहमीडिया प्रभारी आलोक दुबे ने कहा कि संपर्क व संवाद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों का सकारात्मक प्रचार हमारी प्राथमिकता रहेगी।



संभागायुक्त की अध्यक्षता में इंदौर सोसायटी फॉर आर्गन डोनेशन की बैठक सम्पन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में आज एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में इंदौर सोसायटी फॉर आर्गन डोनेशन की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने इंदौर सोसायटी फॉर आर्गन डोनेशन द्वारा किये जा रहे सेवा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखी और उसकी समीक्षा की। बैठक में संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने कहा कि अंगदान के क्षेत्र में इंदौर सोसायटी फॉर आर्गन डोनेशन अच्छा कार्य कर रहा है। कोविड महामारी के उपरांत अंगदान के क्षेत्र में इन्दौर संभाग में उल्लेखनीय प्रगति की गई है, जिसके चलते अनेक नागरिकों को नया जीवन एवं स्वास्थ्य लाभ मिला है। वर्तमान में इन्दौर संभाग में 13 चिकित्सा संस्थान को अंग प्रत्यारोपण की प्रशासनिक अनुमति जारी की गई है, जिसमें 11 चिकित्सा संस्थान सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। जिसमें राजश्री अपोलो हॉस्पिटल, चोईथराम हॉस्पिटल एवं विशेष जुपिटर हॉस्पिटल प्रथम तीन चिकित्सा संस्थान हैं। अंगदान के क्षेत्र में सक्रिय इंदौर सोसायटी फॉर आर्गन डोनेशन की बैठकें लगातार आयोजित जा रही हैं और उसकी समीक्षा भी की जा रही है, ताकि इंदौर संभाग अंगदान के क्षेत्र में प्रदेश और देश में अन्वल बन सके। संभागायुक्त ने कहा कि अंगदान कराने वाले डॉक्टरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जो अंगदान के लिये प्रेरित कर अंगदान कराने में सफलता प्राप्त करेगा, उन्हें सहायता संस्था द्वारा 25 हजार रूपये का इंसेंटिव प्रदान किया जायेगा।

होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने का सुनहरा अवसर

मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग के संस्थान में सीधे एडमिशन की सुविधा



दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग के अंतर्गत संचालित एवं नेशनल कार्टेजिज फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी (एनसीएचएमसीटी) नोएडा से मान्यता प्राप्त स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (एसआईएचएम) इंदौर होटल उद्योग में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभर रहा है। राऊ स्थित यह संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है। साथ ही इंदौर सबसे स्वच्छ शहर होने के साथ यहाँ सौम्य जलवायु, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, उत्कृष्ट

कनेक्टिविटी, आईआईटी-आईआईएम जैसे शीर्ष स्तरीय शैक्षणिक केंद्र होने के कारण विद्यार्थियों की पहली पसंद बना हुआ है। उज्जैन-ऑंकारेश्वर की निकटता और व्यावसायिक गतिशीलता भी इंदौर शहर की प्रमुख विशेषता है। यह जानकारी देते हुए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इंदौर के प्राचार्य डॉ. वी.के. सिंह ने बताया कि एसआईएचएम (राऊ) इन्दौर में पाठ्यक्रम राऊ में स्थित एस.आई.एच.एम. इन्दौर में जवाहरलाल नेहरू वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख कोर्स, बी.एस.सी. हॉस्पिटैलिटी और होटल एडमिनिस्ट्रेशन (3 वर्ष) हेतु नामांकन करा सकते हैं। इसके अलावा, हम 18 महीने का डिप्लोमा कार्यक्रम विभिन्न ट्रेड्स में और 10वीं पासआउट के लिए 6 महीने का × सर्विस एवं 1/2 वर्षीय क्राफ्टसमेंशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। उक्त संस्थान के नये सत्र में प्रवेश हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तीन वर्षीय डिग्री प्रोग्राम बीएससी (हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन) में प्रवेश हेतु नेशनल कार्टेजिज नोयडा और नेशनल टैस्टिंग एजेंसी के सहसंबद्ध द्वारा जाइंट इंटेरा इजाम जेईई इस वर्ष 25 मई 2026 को ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। जो छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित विद्यार्थियों के लिए संस्थान स्तर पर डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा भी उपलब्ध है।

सम्पादकीय

सड़के वही, लेकिन सफर हो रहा महंगा, टोल बढ़ोतरी ने यात्रियों की बढ़ाई मुश्किलें

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एकल और दोहरी यात्रा में पांच रुपए से लेकर पैंतीस रुपए तक की बढ़ोतरी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। देशभर में महंगाई में बढ़ोतरी के बीच अब लोगों के लिए कहीं आना-जाना भी महंगा साबित होने लगा है। दरअसल, वैश्विक परिस्थितियों की वजह से पहले ही संकट का दायरा फैल रहा है और चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस बीच हरियाणा में राजमार्गों पर टोल दरों में बेतहाशा वृद्धि की घोषणा आम लोगों के सामने एक नई परेशानी पैदा करने वाली है। इसके अमल में आने के साथ ही निजी वाहनों से यात्रा करने वालों को अब अधिक टोल चुकाना होगा। यह हाल तब है, जबकि अधिकतर राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, आए दिन लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एकल और दोहरी यात्रा में पांच रुपए से लेकर पैंतीस रुपए तक की बढ़ोतरी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मसलन, गुरुग्राम में द्राका एक्सप्रेस-वे पर बजघेड़ा टोल प्लाजा पर एकल यात्रा के लिए 225 रुपए देना यात्रियों के लिए भारी साबित हो सकता है। दूसरी ओर वाणिज्यिक वाहनों से वसूली का असर भी दिखेगा और आखिरकार आम आदमी पर ही इसकी मार पड़ेगी। सवाल है कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार किए बिना टोल दरों में वृद्धि की क्या तुक है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राजमार्गों पर यात्रा महंगा किए जाने से लोगों में निराशा बढ़ेगी। इस समय ज्यादातर राजमार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। वहीं रास्ते में सफा-सुथरे जन-सुविधा परिसरों का अभाव खफकता है। रात में कई मार्गों पर अंधेरा होने से हादसे का अंदेश बना रहता है। राजमार्ग प्राधिकरण के गश्ती दल तुरंत मौके पर नहीं पहुंचते। इससे लोग असह्य स्थिति में होते हैं। कई बार हादसे के बाद फिर हादसा होना यह बताता है कि प्राधिकरण को टोल की तो चिंता है, लेकिन यात्रियों की जान की नहीं। अक्सर देखा गया है कि टोल नाकों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इससे न केवल समय की, बल्कि ईंधन की भी बर्बादी होती है। हालांकि हरियाणा में टोल पर अब केवल फास्टेज या आनलाइन भुगतान ही किया जा सकेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की कि भारत लगभग माओवादी मुक्त हो चुका है, और उग्रवाद की केन्द्रीय और राज्य स्तरीय नेतृत्व संरचनाएं काफी हद तक ध्वस्त हो चुकी हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि पिछले तीन वर्षों में 4,839 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि शीर्ष समिति के सदस्य या तो मारे गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। घोषणा होते ही लोकसभा सदस्यों द्वारा अमित शाह द्वारा की गई इस घोषणा का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और राहुल गांधी तथा कांग्रेस की नक्सलवादियों को वैचारिक समर्थन देने के आरोप में आलोचना भी की। शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि देश को जल्द ही वामपंथी उग्रवाद की दीर्घकालिक चुनौती से आधिकारिक तौर पर मुक्त घोषित कर दिया जाएगा।

इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई समय सीमा मंगलवार, 31 मार्च को समाप्त हो गई, जिसमें केवल कुछ नक्सली जंगल में बचे थे, वह भी नेतृत्वविहीन राज्य में। समय सीमा के बारे में दरअसल देखा जाय तो किसी समस्या से उत्पन्न होने वाली हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को, पुलिस को समय देने में कोई बुराई नहीं है। ये सही है कि जब तक उन्हें ऐसा टारगेट टास्क नहीं दिया जाता है, तब तक उनके ऑपरेशन को तेज नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि तय समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के बाद भी समस्या खत्म हो जाती है? सवाल नक्सल आंदोलन पर लागू होता है, जो लंबे समय से देश में है और अब सरकार बनने पर है। महानिदेशक के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विजयकुमार ने नक्सल नरसंहार का श्रेय शाह के साथ-साथ चिदंबरम को भी दिया। उनके अनुसार, इस आंदोलन में कांग्रेस और भाजपा दोनों की केंद्र की सरकारों द्वारा दिखाई गई निरंतरता सराहनीय है। रिजर्व बल के पूर्व महानिदेशक, के. दुर्गा प्रसाद ने भी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि नक्सलियों का खात्मा होना अच्छी बात है, लेकिन अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को विकास की प्रक्रिया में लाना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए सरकार को स्थानीय स्तर पर काफी काम करना होगा।

पश्चिम बंगाल में नक्सली विद्रोह को

वामपंथी उग्रवाद को हारने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई



कुचलने के लगभग 45 साल बाद, नक्सलियों ने समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता और सरकार और अमीरों द्वारा किए गए अन्याय के आधार पर दंडकारण्य में प्रभाव पैदा किया। क्या यहां रहने वाले आदिवासी विकास की मुख्यधारा में आ गए हैं? क्या इस दौरान इस क्षेत्र में सरकार की सक्रियता से सामाजिक जीवन में कोई फर्क पड़ा? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास ये पांच चीजें हैं जो विकास को गति देने के लिए जरूरी हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने एक सर्वे किया। इसके मुताबिक 92 फीसदी मीडिया को नहीं पता कि आजादी क्या होती है। बहुत से लोग भाषा और संवैधानिक अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गलती करता है तो उसे शिकायत करनी पड़ती है। 60 प्रतिशत माइडियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। इसके लगभग 48 प्रतिशत निवासियों के पास सरकारी पहचान पत्र नहीं है। मुख्य रूप से वन खेती पर निर्भर इस जनजाति की वार्षिक आय 30,000 रुपये से कम है। हालांकि सर्वे का दायरा दक्षिण गडचिरोली तक ही सीमित है, लेकिन इस बात की संभावना नहीं है कि स्थिति अन्य जगहों से बहुत अलग है। बरतार और अयुजमद गडचिरोली से भी ज्यादा पिछड़े हैं। इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस पृष्ठभूमि में,

यदि हम नक्सलवाद के अंत को देखें, तो यह आसानी से महसूस किया जा सकता है कि नवीनतम सफलता के बाद भी शासकों के सामने चुनौती कितनी कठिन है। नक्सलियों की मौजूदगी विकास में मुख्य बाधा थी और अब जब इसे खत्म कर दिया गया है तो सरकार दावा कर सकती है कि यह क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में आया। इसे स्वीकार करने से पहले कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा। नक्सलियों का रिट्रीट 2012 में शुरू हुआ और देश के 100 जिलों में उनका प्रभाव धीरे-धीरे घटकर 40 रह गया और पिछले दो साल में यह संख्या घटकर एक अंक में आ गई है। सरकार के लिए उन क्षेत्रों में विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना संभव है जहां नक्सलियों ने वर्षों से अपनी उपस्थिति खो दी है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? नक्सली भूपति ने हाल ही में कहा था कि यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए दो कानून - 'वन अधिकार' और 'पेसा' आंदोलन के विकास में मुख्य बाधा थे। इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू क्यों नहीं किया गया? 2014 के बाद ये दो कानून हैं जो गांवों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हैं। गृह मंत्री के रूप में चिदंबरम ने नक्सल विरोधी अभियान चलाते हुए लगातार कानून और व्यवस्था और विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित किया, नक्सल प्रभावित जिलों को सीधे फंड दिया, जो भाजपा के सत्ता में आने

के बाद बंद हो गया और केंद्र ने विकास का मुद्दा राज्य पर छोड़ दिया। पिछले तीन वर्षों में दूर-दराज के क्षेत्रों में ढाई सौ से अधिक सुरक्षा बलों की स्थापना की गई है और सुरक्षा बलों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उन्होंने नक्सलियों को पकड़ने या आत्मसमर्पण करने के अवसर का लाभ उठाया है। लेकिन इसी दौरान खनिज अन्वेषण में सरकार की प्राथमिकता देखी गई। इसे सुरक्षित रूप से करने के लिए, उन गांवों में 80 फुट सड़कें बनाई गईं जहां गांव नहीं थे।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोहे और अन्य खनिजों का खनन औद्योगिक विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन खदानों को पूरे क्षेत्र के विकास के रूप में चिन्तित करना न केवल पूरी तरह से गलत है बल्कि प्रकृति की पूजा करने वाले आदिवासियों के जीवन के तरीके पर भी अतिक्रमण करता है। यह सच है कि कुशल और अकुशल हाथों को काम मिलता है, लेकिन इससे चुनिंदा लोगों के हित नहीं होते हैं और बड़ा वर्ग इससे बंचित रहता है। इस समूह को रोजगार योग्य बनाने के लिए स्कूलों की जरूरत है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ पेयजल, आर्थिक विकास के लिए पारंपरिक कृषि में बदलाव की जरूरत है। क्या उद्योगों के कारण पेड़ों की कटाई और इन सब से होने वाले प्रदूषण, प्रकृति पूजा व्यवस्था को लगे झटके, आदिवासियों का विकास होगा या विनाश? सरकार द्वारा अपनाई गई विकास की वर्तमान प्रौद्योगिकी आदिवासियों को एक और संकट में धकेल रही है, यह सब ठीक है, लेकिन कोई योजना नजर नहीं आ रही है। यह उम्मीद करना गलत है कि शिक्षा की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों में बदलाव के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों का विकास भी होगा। इसका कारण आर्थिक आया है।

इसलिए सरकार को नक्सल मुक्ति का जश्न जरूर मनाना चाहिए, लेकिन जो आदिवासी आज भी अपनी संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं और जंगल बचा रहे हैं, उनके मामले में शहरी विकास के मॉडल पर चलने के बजाय सतत विकास की सोच अपनानी चाहिए। नक्सलियों के खात्मे के बाद अगर खुदाई से जंगल नष्ट नहीं होते हैं तो यह नक्सली मुक्ति सार्थक होगी।

अशोक भाटिया,
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

आंचलिक

250 परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं, बिजली कर्मचारी महासंघ ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन • बिजली कर्मचारी महासंघ ने खरगोन में अपनी लंबित मांगों को लेकर सांकेतिक आंदोलन किया। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में देरी के विरोध में किया गया। महासंघ ने वर्ष 2000 से 2012 के बीच मृत हुए बिजली कंपनी के कर्मचारियों के परिजनों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। कर्मचारी प्रतिनिधियों के अनुसार, प्रदेशभर में ऐसे 2500 कर्मचारी हैं, जिनमें से जिले में 250 कर्मचारियों के परिजनों को अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों पर लंबे समय से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण आंदोलन का निर्णय लिया गया है। सामान्य मृत्यु के मामलों में आश्रित परिवारों को

अनुकंपा नियुक्ति न मिलने से कई परिवार आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति के अलावा, महासंघ की अन्य मांगों में संविदा कर्मचारियों का नियमितकरण, वेतन विसंगति का निराकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था, गृह जिले में स्थानांतरण और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का समय पर भुगतान शामिल है।

इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को समान सुविधाएं देने की मांग भी उठाई गई है। महासंघ ने ग्रेज्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने, पुराने कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने और योग्य डिप्लोमा धारकों को कनिष्ठ अभियंता पद पर नियुक्त करने की मांग भी की है। अगले चरण में, 16 अप्रैल को राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

उपसरपंच कर रहा था शराब तस्करी, घर के पीछे जमीन में गड़ी टंकी मिली

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन • भगवानपुरा क्षेत्र में उपसरपंच शंकरलाल हीरालाल मालवीय के घर से 198 लीटर अवैध देशी और विदेशी शराब जब्त की गई है। आरोपी शंकरलाल पूर्व में जिलाबंदर भी रह चुका है। पुलिस ने यह कार्रवाई भग्यापुर में की। भीकनगांव एसडीओपी राकेश आर्य ने बताया कि आरोपी शंकरलाल पिता हीरालाल मालवीय ने अपने घर के पीछे खाली जमीन में गड्ढा खोदकर एक पानी की टंकी बना रखी थी। इसी टंकी में वह अवैध देशी और विदेशी शराब बेचने के लिए छिपाकर रखता था। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी भगवानपुरा निरीक्षक इलापसिंह मुजाल्दे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान घर के पीछे जमीन में छिपाई गई टंकी मिली। मिट्टी हटाकर जांच करने पर उसमें शराब की पेटियां और पाउच रखे पाए गए। पुलिस ने कुल 68 हजार 625 रुपए मूल्य की 198 लीटर देशी-विदेशी शराब जब्त की। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 36 के तहत कार्रवाई की गई है।



उपसरपंच पर पहले से 6 अपराधिक

मामले दर्ज

आरोपी शंकरलाल मालवीय पर भगवानपुरा थाने में अवैध शराब बिक्री से संबंधित आबकारी अधिनियम के तहत पहले से छह मामले दर्ज हैं। वह गुंडा सूची में भी शामिल है। पुलिस आरोपी के क्षेत्र में फैले नेटवर्क की जांच कर रही है। फिलहाल, शंकरलाल मालवीय उपसरपंच के पद पर है। इससे पहले वह स्थानीय भग्यापुर पंचायत में पंच भी रह चुका है।

खंडवा में मंडल अध्यक्ष ने मोमोस टेले वाले से रोज के 500 रुपए मांगे थे

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा • खंडवा में सोशल मीडिया पर सामने आए बीजेपी मंडल अध्यक्ष के ऑडियो का मामला संगठन स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को खंडवा आए संगठन प्रभारी ने इस मामले में जल्द कार्रवाई होने की बात कही है। ऑडियो में घंटाघर चौक पर लगाने वाले मोमोस के टेले वाले से 500 रुपए रोजाना की मांग की जा रही है। ऑडियो में भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा और एक एमआईसी मंत्री के भतीजे विजय पंचार को टेले वाले से बातचीत है। इसमें टेले वालों से गुंडा टैक्स की तरह वसूली होने का खुलासा होता है। कहा जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष और एमआईसी मंत्री के रिश्तेदार द्वारा टेलेवाले पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। टेले वाले ने कहा कि महीने में सिर्फ 8-10 दिन ही टेला लगा पाता हूं। ऐसे में 500 रुपए देना हैसियत से बाहर रहे हैं, उनके मामले में शहरी विकास के मॉडल पर चलने के बजाय सतत विकास की सोच अपनानी चाहिए। नक्सलियों के खात्मे के बाद अगर खुदाई से जंगल नष्ट नहीं होते हैं तो यह नक्सली मुक्ति सार्थक होगी।

सांसद पाटिल ने रेल मंत्री से की मुलाकात खंडवा बुरहानपुर और नेपालगर ट्रेनों के टहराव की मांग

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा • सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने अपने संसदीय क्षेत्र की रेल सुविधाओं को लेकर केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। नई दिल्ली में हुई यह मुलाकात एक हफ्ते में दूसरी बार थी। उन्होंने खंडवा, बुरहानपुर और नेपालगर क्षेत्र की लंबित रेल मांगों को प्रमुखता से रखा। डीआरयूसीसी सदस्य पंकज नाटानी ने बताया कि सांसद पाटील ने रेल मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के यात्रियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के लिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने ट्रेन संख्या 12533-34 लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस और 07053-54 बीकानेर-कांचीगुड़ा एक्सप्रेस के टहराव की मांग की।



उन्होंने इस संबंध में रेल मंत्री को एक पत्र भी सौंपा।

सांसद ने बताया कि इन ट्रेनों के टहराव

से क्षेत्र के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और लंबी दूरी की यात्रा सुविधाजनक हो सकेगी। इसी प्रकार, नेपालगर स्टेशन के लिए ट्रेन संख्या 17605-06 कांचीगुड़ा-भगत की कोटी एक्सप्रेस के टहराव की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। साथ ही, कोरोना काल में नेपालगर में स्थगित की गई ट्रेनों को पुनः पूर्ववत शुरू करने का अनुरोध किया गया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटील की लगातार सक्रियता के चलते अब क्षेत्र में इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद बढ़ गई है। यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो खंडवा, बुरहानपुर और नेपालगर क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इस मुलाकात के दौरान मध्य रेल समिति के सदस्य मनोज सोनी और नरेंद्र पाटील भी उपस्थित थे।

कॉलोनाइजर को राहत देने से कोर्ट का इनकार, मीन पर कब्जे का सबूत नहीं दे पाए

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा • शहर की जूनी इंदौर लाइन स्थित सुजापुर कला की विवादित जमीन को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कॉलोनाइजर अभय जैन और आयुष जैन को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल रजिस्ट्री, नामांतरण या अन्य दस्तावेजों के आधार पर कब्जा साबित नहीं माना जा सकता, बल्कि मौके पर वास्तविक कब्जा किसका है, यही निर्णायक आधार होगा। यह मामला जमीन को लेकर अभय जैन पक्ष और रितेश गोयल पक्ष के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है। शांति भंग की आशंका के चलते पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 164 के तहत मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह देखना जरूरी है कि विवाद से पहले के 60 दिनों में जमीन पर वास्तविक कब्जा किसका था। जैन पक्ष द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री, नामांतरण और सीमांकन जैसे दस्तावेज कब्जे की स्थिति सिद्ध करने के लिए पर्याप्त

नहीं पाए गए। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि जैन पक्ष ने पहले कब्जा स्थापित करने के लिए कोई ठोस कानूनी कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने मामले को मूल रूप से लेन-देन से जुड़ा सिविल विवाद मानते हुए जैन पक्ष को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी और धारा 164 के तहत राहत देने से इनकार कर दिया।

फैसले के बाद भी विवाद, हथियारों के साथ पहुंचे लोग

कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बावजूद विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया। आरोप है कि अभय जैन के बेटे आयुष जैन और पिता कांतिलाल जैन 10-12 लोगों के साथ जेसीबी और वाहनों में सवार होकर विवादित जमीन पर कब्जा लेने पहुंच गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ लोगों के पास धारदार हथियार थे और कांतिलाल जैन के हाथ में बल्लम जैसा हथियार देखा गया। मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस गई और मामले को शांत कराया।

राजेंद्र भारती ही नहीं, प्रदेश के अन्य विधायक भी कानूनी जाल में उलझे!

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
भोपाल • मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक़्त बयानबाजी या चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं है। अदालतों में भी कई नेताओं की किस्मत तय हो रही है। ताजा मामला दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती का है, जिन्हें 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी केस में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। अब बड़ा सवाल उनकी विधायकी को लेकर है। कानून के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः खत्म हो सकती है। ऐसे में तीन साल की सजा ने भारती की कुर्सी को खतरों में डाल दिया है। हालांकि, उन्हें अपील के लिए 60 दिन का वक़्त मिला। यदि वे हाईकोर्ट से सजा पर स्थगन (स्टे) लेने में सफल हो जाते हैं तो उनकी विधायकी बच सकती है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उनकी सदस्यता पर संकट बना रहेगा। राजेंद्र भारती अकेले नहीं हैं। मध्य प्रदेश में इस समय करीब आधा दर्जन विधायक अलग-अलग कानूनी मामलों में

उलझे हुए हैं। कोई चुनावी विवाद में फंसा है तो कोई दल-बदल, शपथ पत्र या जाति प्रमाण पत्र जैसे मामलों में। आइए समझते हैं, कौन-कौन से विधायक इस समय कानूनी संकट में हैं और उनकी स्थिति क्या है...

1. **मुकेश मल्होत्रा** : राहत मिली, पर खतरा टला नहीं- विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत देते हुए उनकी विधायकी बरकरार रखी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की दलीलों के बाद जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मल्होत्रा को विधायक बने रहने की अनुमति दी है। यह राहत पूरी तरह से आजादी नहीं है। कोर्ट ने साफ किया है कि अंतिम फैसला आने तक वे राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे।

किसी की कुर्सी डांवाडोल तो किसी पर तलवार लटकी



2. **निर्मला सप्रे**: दल-बदल का आरोप, कोर्ट में केस-सागर जिले की बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे का मामला दल-बदल कानून से जुड़ा है। वर्ष 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाली निर्मला सप्रे 5 मई 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बीजेपी कार्यक्रम में नजर आई थीं। इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गईं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर के पास याचिका दायर की, जिसमें संविधान की

10वीं अनुसूची का हवाला दिया गया। जब इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाल ही में सुनवाई के दौरान निर्मला सप्रे ने अदालत में कहा कि वे अब भी कांग्रेस में हैं।

3. **अभय मिश्रा**: हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप- रोवा की सेमरिया सीट से सिर्फ 637 वोटों से जीतने वाले कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा भी कानूनी संकट में हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने से इनकार कर केस को ट्रायल के लिए आगे बढ़ा दिया है।

बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपति त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि मिश्रा ने नामांकन के दौरान अपने शपथ पत्र (फॉर्म-26) में अपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। आरटीआई के जरिए 9 मामलों का हवाला दिया गया है। इसके अलावा उन पर बैंक से लिए गए लोन की जानकारी छिपाने का भी आरोप है। दावा है कि 23 लाख का लोन बढ़कर 50 लाख से ज्यादा हो गया था, जिसे उन्होंने घोषित नहीं किया।

4. **आरिफ मसूद**: सुप्रीम कोर्ट से राहत, पर मामला खत्म नहीं- भोपाल मध्य से कांग्रेस

विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ फर्जी सेल डीड से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मामला इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को एफआईआर दर्ज करने और डीजीपी को एसआईटी गठित करने तक के निर्देश दिए थे।

मसूद ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्हें राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश देना उचित नहीं था।

5. **गौतम डेटवाल**: जाति प्रमाण पत्र विवाद में फंसे मंत्री- सारंगपुर से विधायक और राज्यमंत्री गौतम डेटवाल जाति प्रमाण पत्र विवाद में घिरे हुए हैं। इंदौर हाईकोर्ट में इस मामले में कई विरोधाभासी दस्तावेज सामने आए हैं।

याचिकाकर्ता कोमलप्रसाद शाक्य का आरोप है कि डेटवाल ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था। उनके अनुसार, पुराने रिकॉर्ड में उनकी

जाति 'जीनगर' दर्ज है, जबकि नए दस्तावेजों में 'मोची' बताया गया है।

6. **संजय पाठक**: जज को फोन करना पड़ा भारी- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विजयराघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक के खिलाफ क्रिमिनल कंटेंट की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामला न्यायाधीश को फोन कर केस पर चर्चा करने की कोशिश से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर हस्तक्षेप माना है।

हाईकोर्ट ने इस केस को अत्यंत गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया और साफ किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब विधायक संजय पाठक के खिलाफ विधिवत क्रिमिनल कंटेंट का मामला दर्ज होगा। यह मामला कटनी के सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष दीक्षित की याचिका से सामने आया है। याचिका माइनिंग से जुड़े आरोपों को लेकर दायर की गई थी, जिसमें विधायक पर गंभीर सवाल उठाए गए थे।

अगले दो दिनों में 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान

दैनिक इंदौर संकेत
इंदौर • गुरुवार शाम को सूरज ढलते ही तापमान में बदलाव शुरू हो गया। तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के साथ बूँदा-बाँदी भी हुई। गुरुवार को तूफानी हवाओं के बीच बूँदा-बाँदी देखने को मिली। इस बदलते मौसम के कारण आगामी दिनों में तापमान में कभी गिरावट देखने को मिलेगी। अगले कुछ ही दिनों में पारा 3 से 4 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। मौसम केंद्र के अनुसार गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। वहीं बुधवार को यह 36.5 डिग्री रहा था। वहीं बुधवार रात से गुरुवार सुबह के बीच न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री और एक रात पहले की अपेक्षा 1.6 डिग्री ज्यादा था।

शिवाजी मार्केट की 16 दुकानें टूटेंगी अंडरग्राउंड मेट्रो को मिलेगा रास्ता

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नगर निगम के खाते में जमा किए डेढ़ करोड़ रुपए

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
इंदौर • मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा अंडरग्राउंड मेट्रो निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया गया है यह काम शहर के मध्य क्षेत्र में तेजी से चल रहा है, जिसमें नगर निगम के मार्केट, पुलिस थाना और दुकानें सहित अन्य निर्माण बाधक बन रहे हैं, जिसको हटाने का काम जल्द ही शुरू होगा। वर्तमान में नगर निगम मुख्यालय के पास मराठी स्कूल परिसर के पीछे अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए खुदाई जारी है। टीबीएम के लिए रास्ता हो रहा तैयार- यहां टनल बोरिंग मशीन के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। आगामी समय में यहां से टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से खुदाई की जाएगी। इस काम के लिए नगर निगम की शिवाजी मार्केट की

16 दुकानें हटाई जाएंगी। फिलहाल मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जितनी जमीन की आवश्यकता है, मार्केट से केवल उसी हिस्से की दुकानें हटाई जा रही हैं, जिसके लिए निगम के खाते में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने निगम के खाते में गुरुवार को डेढ़ करोड़ रुपए जमा किए हैं। अंडरग्राउंड खुदाई का डर दूर करने प्रयास निगम एवं मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में स्पष्ट कर दिया है कि मेट्रो निर्माण के दौरान किसी भी रहवासी के मकान को नहीं हटाया जाएगा। क्षेत्र में मकान हटाने अंडरग्राउंड खुदाई को लेकर रहवासियों में दशहट थी, लेकिन मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अधिकारी और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की समझाइश के बाद रहवासियों का डर दूर हुआ है।



अगले सप्ताह हटाई जाएंगी दुकानें-मार्केट विभाग के अपर आयुक्त आकाश सिंह ने बताया कि इधर नगर निगम द्वारा शिवाजी मार्केट की जमीन देने पर सहमति बन गई है, साथ शिवाजी मार्केट

हटाने को लेकर भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यहां की सभी 125 दुकानें हटाई जाएंगी। नगर निगम ने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से डेढ़ करोड़ रुपए की राशि निगम से डिमांड की थी, क्योंकि 16 दुकानें हटाई जानी

हैं। ये दुकानें खाली करवा ली गई हैं। बीते एक साल से दुकानें हटाने नोटिस निगम की ओर दुकानदारों को दिए हैं। वहीं, अपर आयुक्त सिंह ने बताया कि मल्हारगंज थाना और यहां बनी दुकानें भी हटाई

रिवर फ्रंट विकसित करने में देरी
महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि शिवाजी मार्केट पर रिवर फ्रंट डेवलप करने की योजना पिछले साल बनाई गई थी, लेकिन मार्केट हटाने में विलंब रहा है। यहां मेट्रो खुदाई पूरी होने के बाद रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। हालांकि जब तक मेट्रो का काम चलेगा, यह संभव नहीं है। सभी जायज दुकानदारों के लिए नंदलालपुरा सब्जी मंडी के पास बनाए गए मार्केट में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।

जानी है। लगभग पांच दुकानें मल्हारगंज थाने की बाउंड्रीवॉल से लगी हुई हैं जिन्हें हटाया जाएगा।

सिमरोल में सरकारी नाले पर अतिक्रमण

जनहित याचिका दायर; प्राकृतिक जल निकासी मार्ग बाधित करने का मामला, कॉलोनाइजर सहित अन्य को नोटिस

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
इंदौर • डॉ. अंबेडकर नगर (महू) तहसील के सिमरोल गांव में सरकारी भूमि और प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली पर कथित अतिक्रमण को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस रिट याचिका में सर्वे नंबर 890 पर दर्ज सार्वजनिक भूमि के संरक्षण के लिए कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। गुरुवार को मामले में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कॉलोनाइजर सहित अन्य को नोटिस जारी कर तलब किया गया है।

राजस्थान अभिलेखों के अनुसार सर्वे नंबर 890 सरकारी नाले/प्राकृतिक जल मार्ग के रूप में दर्ज है, जो क्षेत्र की प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानसून के दौरान इस



मार्ग से भारी मात्रा में वर्षा जल बहता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कॉलोनाइजर राजू पेंड्रावाला, अनुराग पांडिया और उनकी फर्म पेंड्रावाला एस्टेट ने सर्वे नंबर 889 स्थित अपनी निजी भूमि पर 'विराज ग्रीन्स' नामक आवासीय कॉलोनी विकसित करते समय उससे सटी सरकारी भूमि (सर्वे नंबर 890) पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया। आरोप है

कि प्राकृतिक जल निकासी मार्ग में मिट्टी और निर्माण मलबा डालकर उसे संकरा कर दिया गया, जिससे पानी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट श्रेष्ठि कुमार चौकसे ने तर्क दिए कि इस प्रकार का अवैध कब्जा न केवल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, बल्कि इससे आसपास के रहवासियों,

सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और पास स्थित एक सरकारी कन्या छात्रावास को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और जलभराव की स्थिति से बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिला कलेक्टर और सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ को शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। कानूनी आधार के रूप में याचिका में मप्र हाई कोर्ट के पूर्व निर्णय उभरे संकरा कर दिया गया, जिससे ग्राम पंचायत धूमा बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) का हवाला दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि 'निस्तार भूमि', 'चनोई', 'तालाब', 'नदी' या अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

करोड़ों का एमवाय अस्पताल, फिर भी 'जुगाड़' से निकाल रहा है समाधान

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
इंदौर • प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम वाय अस्पताल में सीपेज की समस्या दूर करने के लिए अब 'जुगाड़ तकनीक' अपनाई जा रही है। अस्पताल की छतों पर हेलोजन लाइट लगाकर दीवारों और छत की नमी को सुखाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद यह व्यवस्था चर्चा का विषय बन गई है। अस्पताल के अंदर छत पर ट्यूब लाइट के साथ अस्थायी तरीके से हेलोजन और खुले तार लटकते नजर आ रहे हैं। इन हेलोजन का उपयोग सीपेज वाली जगहों को गर्म कर नमी खत्म करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार यह केवल अस्थायी उपाग है और इससे समस्या जड़ से खत्म नहीं होती। ओटी कॉम्प्लेक्स एक साल से बंद- सीपेज की गंभीरता का

सुरक्षा पर भी उठ रहे सवाल
छत पर खुले तारों और अस्थायी फिटिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की व्यवस्था मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, शार्ट्स/किट से आग भी लग सकती है। हेलोजन लगाकर सीपेज सुखाने की यह कोशिश भले ही फिलहाल नाहत दे रही हो, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर करोड़ों की लागत से संचालित इस बड़े अस्पताल में बुनियादी समस्या का स्थायी हल कब निकलेगा। इस पूरे मामले ने अस्पताल प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखा होगा कि जिम्मेदार विभाग इस 'जुगाड़ मॉडल' से आगे बढ़कर कोई ठोस और स्थायी समाधान कब तक निकालते हैं।

अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रथम मंजिल पर बना अत्याधुनिक ऑर्परेशन थिएटर (ओटी) कॉम्प्लेक्स करीब एक साल से तैयार होने के बावजूद शुरू नहीं हो पाया है। नमी और लीकेज के कारण यहां हाई-टेक मशीनें इंटॉल नहीं की जा सकीं। जानकारी के मुताबिक,

सीपेज की समस्या खत्म करने के लिए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से अब तक लाखों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके तहत नई ड्रेनेज पाइपलाइन डाली गई। टॉयलेट्स का रिनोवेशन किया गया। उत और दीवारों की मरम्मत कराई गई। इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।

प्रदेश की 5,600 फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर 20 हजार कर्मचारियों को निकाला

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
इंदौर • ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर अब मध्य प्रदेश के 'डेट्रॉयट' कहे जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर पर साफ दिखने लगा है। उद्योग संचालकों का कहना है कि हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाला समय उद्योगों और मजदूरों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष डॉ. गौतम कोठारी के मुताबिक, यहां से होने वाला एक्सपोर्ट लगभग पूरी तरह रुक गया है। कच्चे माल की महंगाई और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग संकट के चलते उद्योगपति प्रोडक्शन घटा रहे हैं। इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा है। फैक्ट्रियों में शिफ्ट कम हो

रही हैं। कई जगह शट-डाउन की स्थिति बन गई है। सबसे ज्यादा असर अस्थायी मजदूरों पर पड़ा है। अनुमान है कि करीब 20 हजार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम से बाहर हो चुके हैं। वहीं कई कंपनियों ने स्थायी कर्मचारियों को भी ले-ऑफ (छंटनी) पर डालकर आधी सैलरी देना शुरू कर दिया है।

पांच दिन से काम बंद, हमारी छुट्टी कर दी गई
सेज सेक्टर की एक फार्मा कंपनी में काम करने वाले लेबर नीतेश बघेल ने बताया- मैं प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता हूँ। कंपनी में प्लास्टिक दाना महंगा होने से 5 दिन से काम बंद है, इसलिए हमारी भी छुट्टी कर दी गई।

सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही
पीथमपुर औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि ऐसी क्राइसिस में हम सरकार का मुंह देखते हैं। बाकी समय तो सरकार हमारा मुंह देखती है, क्योंकि हम उन्हें टेक्स देते हैं। उन्हें जीडीपी में योगदान देते हैं, अगर आपने गैस कम कर दी तो यह कोई क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट तो तब होता, जब इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुसार हर चीज का निर्धारण होता है। सरकार समस्या को नकारते हुए बाहरी रूप से अगर उसे मैनेज कर रही है तो यह क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं, बल्कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है।

न्याय नगर संस्था की जमीन पर बसी अवैध कृषाबाग कॉलोनी के मकान तोड़े जाएंगे

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
इंदौर • एमआर-10 से लगी न्याय नगर संस्था की जमीन पर बसी अवैध कृषाबाग कॉलोनी के 71 मकान पूरी तरह से टूटेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में यहां के रहवासियों को हार मिली है। पांच साल से चल रही इस लड़ाई में जुलाई 2024 में 15 से ज्यादा मकान बारिश के बीच टूटे थे। इसके बाद भी छुटपुट कार्रवाई हुई थी, फिर स्टे आने के बाद मामला अटक गया था। इसके बाद श्रीराम बिल्डर्स ने फिर कोर्ट की शरण ली थी, वहां से जिला प्रशासन को जमीन खाली करवाने के आदेश मिले हैं। इसी के बाद जूनी इंदौर तहसील में आने वाली इस कॉलोनी के 71 मकानों को तोड़ने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है।

कई दिनों से मोके पर निशान भी लगाए जा रहे थे और नोटिस भी जारी हुए थे। अब लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। संभवतः इसी सप्ताह यहां कार्रवाई हो भी जाएगी। यहां जो मकान बने हैं, उनमें हर रहवासी की अपनी कहानी है। कोई निमाड़ से आकर यहां बसा तो कोई भिंड-मुंरना या ग्वालियर से। एक रहवासी ने किसी नागर नामक व्यक्ति से 10.50 लाख में प्लॉट खरीदा था। तब नागर ने भरोसा दिलाया था कि सब कुछ लीगल है। जुलाई 2024 में अचानक नोटिस आया और मकान टूट गया। परिवार को किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। इसी तरह यादव परिवार ने बताया कि 12 साल पहले मोहसिन नामक व्यक्ति से 4 लाख रुपए में प्लॉट खरीदा था। फिर मकान

बनाया। चार बेटियां और एक बेटा है। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि जिस व्यक्ति को प्लॉट बेचा था, मैंने उनसे 2014 में दोनों मकान खरीदे थे। इसमें से एक मकान में किराएदार थे, दूसरा खाली था। मुझे नोटिस की जानकारी नहीं मिली। एक हफ्ते पहले टीम क्रॉस का निशान लगाकर चली गई। मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स तर्फे पार्टनर शशि भूषण खडेलवाल ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका 2023 में दायर की। इसमें 25 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित कर 45 दिन में अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश किए गए। इसका पालन न होने पर मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स ने अवमानना याचिका (109/2024) लगाई।

करीब 20 हजार कर्मचारियों को निकाला